## Q. नीति आयोग नीति निर्माण में कैसे योगदान करता है? विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।

परिचय

नीति आयोग (National Institution for Transforming India – NITI Aayog) भारत सरकार का सर्वोच्च नीति-निर्माण एवं विचार मंच (Think Tank) है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तथा राज्यों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए सरकार ने महसूस किया कि केवल केंद्रीकृत योजना प्रणाली से देश का समग्र विकास संभव नहीं है। इसलिए एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता थी जो सरकार को नीतिगत सलाह, अनुसंधान, नवाचार, सहकारी संघवाद तथा साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करे। इसी उद्देश्य से नीति आयोग की स्थापना हुई।

नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" की भावना के साथ भारत को समावेशी, टिकाऊ, आधुनिक तथा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। यह संस्था स्वयं धन का आवंटन नहीं करती, बल्कि सरकार को नीतियाँ बनाने, उनका मूल्यांकन करने तथा उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।

### नीति आयोग का नीति निर्माण में योगदान

#### 1. राष्ट्रीय विकास की दिशा निर्धारित करना

नीति आयोग देश के दीर्घकालीन विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण तैयार करता है। यह वर्तमान परिस्थितियों, भविष्य की आवश्यकताओं तथा वैश्विक चुनौतियों का अध्ययन करके ऐसी नीतियाँ सुझाता है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक हों। यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास के लक्ष्य निर्धारित करता है तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति भी तैयार करता है।

#### 2. केंद्र सरकार को नीतिगत सलाह देना

नीति आयोग सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को नीतिगत सलाह देता है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जल संरक्षण, कौशल विकास, रोजगार, वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक न्याय जैसे अनेक क्षेत्रों में यह विशेषज्ञ सुझाव प्रदान करता है।

इस प्रकार सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियाँ अधिक वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा जनहितकारी बनती हैं।

#### 3. राज्यों के साथ सहयोग स्थापित करना (सहकारी संघवाद)

भारत एक संघीय देश है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीति आयोग राज्यों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करता है। राज्यों के मुख्यमंत्री, अधिकारी तथा विशेषज्ञ नीति आयोग की बैठकों में भाग लेते हैं और अपने सुझाव देते हैं।

इससे राज्यों की स्थानीय समस्याएँ, संसाधन तथा आवश्यकताएँ नीति निर्माण में शामिल हो जाती हैं। यही कारण है कि नीति आयोग को सहकारी संघवाद का प्रमुख संस्थान माना जाता है।

#### 4. प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना

नीति आयोग राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित करता है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, नवाचार, जल प्रबंधन, सतत विकास, निर्यात तथा निवेश के आधार पर राज्यों का प्रदर्शन मापा जाता है।

जब राज्यों को अपनी रैंकिंग सुधारने की प्रेरणा मिलती है, तो वे बेहतर योजनाएँ बनाते हैं और विकास की गति तेज होती है।

### 5. साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण

नीति आयोग केवल अनुमान या राजनीतिक विचारों के आधार पर नीतियाँ नहीं बनाता, बल्कि आँकड़ों, सर्वेक्षणों, अनुसंधान, विशेषज्ञों की रिपोर्टों तथा अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का अध्ययन करके सुझाव देता है।

इससे नीतियाँ अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा परिणाम देने वाली बनती हैं।

### 6. दीर्घकालीन, मध्यमकालीन एवं अल्पकालीन योजनाएँ

नीति आयोग ने देश के विकास के लिए विभिन्न समयावधि की योजनाएँ तैयार की हैं–

15 वर्षीय दृष्टि दस्तावेज (Vision Document)

7 वर्षीय रणनीति (Strategy)

3 वर्षीय कार्ययोजना (Action Agenda)

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार को स्पष्ट दिशा मिलती है कि आने वाले वर्षों में किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है।

### 7. सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी

नीति आयोग केवल नीतियाँ बनाने तक सीमित नहीं रहता बल्कि उनके क्रियान्वयन की भी निगरानी करता है।

यह देखता है कि योजनाओं का लाभ वास्तव में लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं। यदि किसी योजना में कमियाँ पाई जाती हैं तो सुधार हेतु सुझाव दिए जाते हैं।

इससे सरकारी योजनाओं की गुणवत्ता तथा पारदर्शिता बढ़ती है।

### 8. नवाचार एवं स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा

आधुनिक अर्थव्यवस्था में नवाचार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।

नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission) की शुरुआत की जिसके माध्यम से–

अटल टिंकरिंग लैब

अटल इन्क्यूबेशन सेंटर

स्टार्टअप को सहायता

वैज्ञानिक अनुसंधान

नई तकनीकों का विकास

जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

इससे युवाओं में वैज्ञानिक सोच तथा उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है।

### 9. डिजिटल भारत और नई तकनीकों को बढ़ावा

नीति आयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, ड्रोन, डिजिटल गवर्नेंस तथा डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों को सरकारी नीतियों में शामिल करने के लिए सुझाव देता है।

इससे प्रशासन अधिक पारदर्शी, तेज़ तथा कुशल बनता है।

### 10. सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) को भारत में लागू करने का प्रमुख दायित्व नीति आयोग निभाता है।

इन लक्ष्यों में–

गरीबी समाप्त करना

भूख मिटाना

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

बेहतर स्वास्थ्य

लैंगिक समानता

स्वच्छ जल

स्वच्छ ऊर्जा

जलवायु संरक्षण

सतत आर्थिक विकास

जैसे उद्देश्य शामिल हैं।

नीति आयोग इन लक्ष्यों की प्रगति का नियमित मूल्यांकन करता है।

### 11. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme)

देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया।

इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जल संसाधन, आधारभूत संरचना तथा वित्तीय समावेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

डेटा के आधार पर जिलों का प्रदर्शन मापा जाता है तथा बेहतर कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहित किया जाता है।

### 12. कृषि क्षेत्र में योगदान

नीति आयोग किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक खेती, सिंचाई, जैविक खेती, कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि तकनीक के उपयोग के लिए सरकार को सुझाव देता है।

यह कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु दीर्घकालीन रणनीतियाँ तैयार करता है।

### 13. स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने, पोषण स्तर बढ़ाने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारने तथा स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाने में नीति आयोग महत्वपूर्ण सुझाव देता है।

### 14. शिक्षा एवं कौशल विकास

नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगारोन्मुख शिक्षा के क्षेत्र में नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देता है।

### 15. पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन

नीति आयोग स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, हरित विकास तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियाँ बनाने में सरकार का सहयोग करता है।

### 16. आर्थिक सुधारों में योगदान

नीति आयोग निवेश बढ़ाने, उद्योगों को प्रोत्साहन देने, रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि, बुनियादी ढाँचे के विकास, विनिर्माण तथा "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसी पहलों को मजबूत बनाने के लिए सुझाव देता है।

### 17. जनभागीदारी और विशेषज्ञों की भागीदारी

नीति आयोग नीति निर्माण में केवल सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि विश्वविद्यालयों, उद्योगों, वैज्ञानिकों, सामाजिक संगठनों, निजी क्षेत्र तथा नागरिकों के सुझावों को भी महत्व देता है।

इससे नीतियाँ अधिक लोकतांत्रिक तथा व्यवहारिक बनती हैं।

### 18. वैश्विक अनुभवों का उपयोग

नीति आयोग विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, OECD तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अनुभवों का अध्ययन करता है और भारत की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त नीतियाँ तैयार करने में सरकार की सहायता करता है।

### 19. पारदर्शिता एवं सुशासन को बढ़ावा

नीति आयोग ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन निगरानी, प्रदर्शन मूल्यांकन तथा जवाबदेही को बढ़ावा देता है। इससे भ्रष्टाचार कम करने तथा प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाने में सहायता मिलती है।

नीति आयोग की प्रमुख उपलब्धियाँ

अटल इनोवेशन मिशन का सफल संचालन।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से पिछड़े जिलों का विकास।

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की निगरानी।

डिजिटल परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय रणनीति।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों में अनेक सुधारात्मक सुझाव।

राज्यों के बीच सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करना।

## निष्कर्ष

नीति आयोग भारत के विकास की दिशा तय करने वाला एक आधुनिक, गतिशील और प्रभावशाली नीति-निर्माण संस्थान है। यह केवल सरकार को सलाह देने तक सीमित नहीं है, बल्कि शोध, आँकड़ों, नवाचार, तकनीक, राज्यों के सहयोग और जनभागीदारी के माध्यम से बेहतर नीतियों का निर्माण सुनिश्चित करता है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में नीति आयोग भारत को आत्मनिर्भर, विकसित, समावेशी, प्रतिस्पर्धी और सतत अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए नीति आयोग को भारत के विकास का विचार मंच (Think Tank) और नीति निर्माण की आधारशिला माना जाता है।